ALFAAZ TIMES

हर खबर, हर शहर

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION UNDER PROCESS
Application No. MAHMUL/2023/88574

GST GSTIN

UDYAM REGISTERED

DIGITAL NEWS NETWORK
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.alfaaztime.digital
info@alfaaztime.digital
+91
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

राजनीति

पश्चिम बंगाल CM सुवेंदु अधिकारी ने नई औद्योगिक नीति के लिए एकता की अपील की



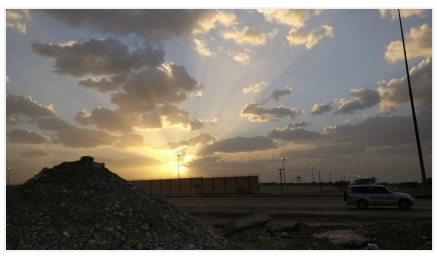
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की आगामी औद्योगिक नीति को आकार देने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक सहज और एकजुट दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि यह नीति क्षेत्रीय आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति को प्रभावी ढंग से समर्थन कर सके।

एकता की यह अपील संकेत देती है कि इस नई नीति के निर्माण में उद्योग नेताओं, सरकारी निकायों और संभवतः राजनीतिक गुटों सहित कई हितधारकों का शामिल होना शामिल है। एक सहयोगात्मक वातावरण बनाकर, प्रशासन एक मजबूत ढांचे का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है जो औद्योगिक क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है।

यह पहल पश्चिम बंगाल के औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी नीति-निर्माण की जटिल प्रक्रिया में सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतिम दस्तावेज राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।

बिज़नेस

जय बलाजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल में स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹6000 करोड़ निवेश की योजना बनाई



जय बलाजी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल में स्टील और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में ₹6000 करोड़ निवेश की योजना का खुलासा किया है।

इस निवेश के तहत नई स्टील उत्पादन सुविधाएँ और सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विकास शामिल है।

उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा।

समूह ने अभी तक विस्तृत समयरेखा का खुलासा नहीं किया है, पर परियोजना अनुमोदन चल रहे हैं।

राजनीति

वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ने सिंगुर के लिए कदम उठाने का वादा किया



वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि राज्य सिंगुर की लंबी अवधि की समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदम उठाएगा।

यह घोषणा राज्य में नई उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक नई पहल के तहत की गई है। बनर्जी ने जोर दिया कि सिंगुर के मुद्दों को हल करना इस व्यापक औद्योगिक रणनीति का प्राथमिक लक्ष्य है।

विशिष्ट उपायों का अभी विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वे क्षेत्र में भूमि और नीति संबंधी चुनौतियों को पुनः देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस कदम से निवेशकों का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है और वेस्ट बंगाल के औद्योगिक कोर में नए प्रोजेक्ट्स के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

बिज़नेस

कोलकाता: बुक किया हुआ फ्लैट बेचने पर बिल्डर को 6.8 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश



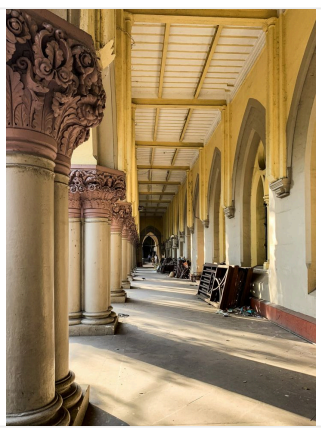
कोलकाता के दो भाइयों को एक प्रॉपर्टी डेवलपर द्वारा उनके बुक किए गए फ्लैट को किसी अन्य पक्ष को बेचने के बाद मुआवजा दिया गया है। भाइयों ने शुरू में 2020 में 10.4 लाख रुपये में फ्लैट बुक किया था और बिल्डर को 5.75 लाख रुपये का भुगतान किया था।

समझौता होने के बावजूद, डेवलपर ने बुक की गई संपत्ति को एक अलग खरीदार को बेच दिया। डेवलपर के इस कदम के बाद, भाइयों को अपने फ्लैट का कब्जा पाने या भुगतान की गई राशि की वापसी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

अन्य माध्यमों से प्रयास करने के बाद, भाइयों ने अपना मामला उपभोक्ता आयोग में ले जाया। आयोग ने डेवलपर को अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया और उन्हें मुआवजे के रूप में पीड़ित खरीदारों को 6.8 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

राजनीति

परिसीमन विवाद के कारण कोलकाता निकाय चुनाव अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक



कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आगामी कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह न्यायिक हस्तक्षेप शहर के भीतर वार्डों के परिसीमन से संबंधित विवाद के जवाब में आया है।

अदालत के इस फैसले का मतलब है कि नागरिक चुनावों के आयोजन की दिशा में औपचारिक घोषणा और बाद के कदम निलंबित रहेंगे। यह रोक विशेष रूप से वार्ड परिसीमन के मौजूदा मुद्दों के समाधान से जुड़ी हुई है। जब तक इन मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक अधिसूचना के साथ चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।

इस घटनाक्रम का केएमसी चुनावों की समय-सीमा पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में देरी हो रही है। रोक की सटीक अवधि परिसीमन विवाद के समाधान पर निर्भर करती है।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल ने नौकरियों के सृजन पर केंद्रित नया निवेश नीति जारी किया



पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरियों के सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई निवेश नीति का ऐलान किया है। यह ढांचा नए प्रोजेक्ट्स द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या से प्रोत्साहन को सीधे तौर पर जोड़कर औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नीति का एक प्रमुख पहलू प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए विशेष प्रोत्साहनों की उपलब्धता है। औद्योगिक उपकरणों के खरीद दाम पर बोझ कम करके, राज्य सरकार निर्माण और औद्योगिक सेटअप को अधिक आकर्षक बनाना चाहती है।

यह कदम 'जॉब-लिंक्ड ग्रोथ' मॉडल की ओर रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जहाँ वित्तीय लाभ ملموس रोजगार परिणामों पर निर्भर करते हैं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि औद्योगिक विकास स्थानीय कार्यबल के लिए सीधे लाभदायक हो।

औद्योगिक विकास के लिए एक स्पष्ट और संरचित तंत्र प्रदान करके, यह नीति निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने और स्थिर आर्थिक विस्तार को सुनिश्चित करने की उम्मीद रखी जा रही है।

राजनीति

अभिशेक बनर्जी के घर पर हमले को लेकर बीजेपी-टीएमसी में तनातनी



अभिशेक बनर्जी के निवास पर हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। इस घटना ने विपक्षी दलों का ध्यान खींचा है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच एक सार्वजनिक बहस शुरू हो गई है।

यह विवाद मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि इस घटनाक्रम के दौरान 'उसे मारने के लिए किसके पास समय है?' जैसा एक टिप्पणी की गई थी। यह बयान राजनीतिक टिप्पणी का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है, जहाँ दोनों पक्षों ने राज्य में कानून-व्यवस्था के संदर्भ में अपनी-अपनी कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया है।

बीजेपी ने इस घटना का उपयोग करके सत्ताधारी पार्टी की जनता की सुरक्षा प्रबंधन की आलोचना की है, जबकि टीएमसी ने बचाव की स्थिति में प्रतिक्रिया दी है और दोष को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की है। यह शब्द युद्ध राज्य में चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को उजागर करता है, जहाँ प्रमुख नेताओं से जुड़ी सुरक्षा घटनाएं अक्सर व्यापक राजनीतिक बहस में बदल जाती हैं।

वर्तमान में, यह घटना पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, जहाँ दोनों पक्ष सार्वजनिक राय को प्रभावित करने के लिए मीडिया में आपस में बहस कर रहे हैं।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल नई औद्योगिक नीति से निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है



पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने हाल ही में एक बयान में राज्य की नई औद्योगिक नीति पर प्रकाश डाला, यह रेखांकित करते हुए कि यह निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। दासगुप्ता ने कहा कि नीति पश्चिम बंगाल को उन व्यवसायों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करती है जो भारत में विस्तार या संचालन स्थापित करना चाहते हैं। नीति और निवेशकों के लिए इसके विशिष्ट प्रोत्साहनों के विवरण अभी तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास के रूप में आती है।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल में जल्द ₹1 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद: सुवेंदु अधिकारी



विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में निकट भविष्य में ₹1 लाख करोड़ के बराबर निवेश की एक महत्वपूर्ण आमद देखने की उम्मीद है। निवेश में यह संभावित वृद्धि अगले कुछ महीनों के भीतर साकार होने की उम्मीद है।

अधिकारी ने ये टिप्पणियां कीं, जो राज्य की आर्थिक संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती हैं। इस अनुमानित निवेश में शामिल विशिष्ट क्षेत्रों या कंपनियों का विवरण नहीं दिया गया है।

यह घोषणा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक संभावित बढ़ावा का सुझाव देती है, हालांकि इन निवेशों की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में अधिक विवरण प्रतीक्षित हैं।

राजनीति

ममता बानर्जी ने दी दिवाली की शुभकामनाएँ, भाजपा पर किया निशाना



दिवाली पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बानर्जी ने लोगों को शुभकामनाएँ देते हुए एक संदेश पोस्ट किया। उसी पोस्ट में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पार्टी की कुछ नीतियों की आलोचना की। यह टिप्पणी राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार के बीच बढ़ती राजनीतिक तनाव के बीच आई। भाजपा से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

अपराध

कलकत्ता में रील बनाने के लिए आदमी को पेट्रोल पिलाकर आग लगाई गई, 3 गिरफ्तार



कलकत्ता पुलिस ने एक भयानक घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक व्यक्ति को सोशल मीडिया रील बनाने के लिए पेट्रोल पीना पड़ता है और उसके बाद उस पर आग लगा दी जाती है। आरोपियों ने ऑनलाइन ध्यान आकर्षित करने के लिए यह अत्याचारपूर्ण कार्य किया था।

यह घटना उस बढ़ते हुए रुझान को दर्शाती है जिसमें लोग ऑनलाइन प्रसिद्धि पाने के लिए हद से परे और खतरनाक तरीकों का सहारा ले रहे हैं। पीड़ितों और गवाहों के अनुसार, आरोपियों ने मजबूरी में व्यक्ति को ज्वलनशील तरल पदार्थ पीने के लिए बाध्य किया और फिर उसमें आग लगा दी।

हमला की जानकारी मिलते ही स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। तीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति वर्तमान में पुलिस हिरासत में हैं, जहाँ उनकी पूछताछ की जा रही है।

प्रशासन ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हानिकारक या हिंसक सामग्री बनाने से जुड़ी गंभीर कानूनी परिणामों को रेखांकित करता है।

राजनीति

बंगाल CM ने पुलिस बल की कमियों पर उठाया सवाल, भर्ती और प्रशिक्षण का वादा किया



पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य के पुलिस बल में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों का उल्लेख किया है, जिसमें वर्तमान संचालन क्षमताओं में कमी शामिल है। हाल ही में दिए गए एक भाषण के दौरान, नेतृत्व ने राज्य भर में बेहतर कानून और व्यवस्था प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री ने एक व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का वादा किया है। इस कदम का उद्देश्य पुलिस विभाग की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि राज्य द्वारा सामने आने वाली विविध सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों।

शक्तियों को बढ़ाने के अतिरिक्त, प्रशासन ने कठोर प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया है। इस योजना में प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और विधियों को अपग्रेड करना शामिल है, जिससे पुलिस कर्मियों के व्यावसायिक कौशल और तैनाती तैयारी में सुधार होगा।

इन उपायों का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक बनाना और इसकी दक्षता को बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि ये कदम पश्चिम बंगाल में एक अधिक प्रतिक्रियाशील और प्रभावी कानून प्रवर्तन एजेंसी को जन्म देंगे।

राजनीति

अभिषेक बनर्जी के घर पर हमले का आरोप: ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया निशाना



पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुत्र अभिषेक बनर्जी के निवास पर हुए संदिग्ध हमले के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना पर राजनीतिक नेताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दल पर कड़ी आलोचना की है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पर हुए इस संदिग्ध हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घटना को विपक्ष की एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य शासक परिवार को निशाना बनाना और अस्थिरता फैलाना है। मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां राज्य में राजनीतिक वातावरण को और अधिक ध्रुवीकृत कर रही हैं।

भाजपा नेता दिलीप घोष ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें खारिज किया और ऐसे आरोपों के पीछे की प्रेरणा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस आरोप का समय संदिग्ध है, जिससे यह संकेत दिया गया कि शासक दल वास्तविक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के बजाय इस घटना का राजनीतिक लाभ उठा रहा है। घोष की टिप्पणियों से राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच गहरी दरार स्पष्ट होती है।

यह घटना पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में एक नया मोड़ साबित हो रही है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों में पुलिस रिपोर्ट के विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे, लेकिन तृणमूल और भाजपा नेताओं के बीच इस तरह की बहस से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में राजनीतिक संवेदनशीलता के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल ने नई औद्योगिक नीति जारी की, आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा



पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति का आधिकारिक रूप से अनावरण किया है, जो राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम का उद्देश्य औद्योगिक विकास के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रदान करना और राज्य को व्यवसायों के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

हालाँकि प्रारंभिक घोषणा में विशिष्ट संख्यात्मक लक्ष्य विस्तार से नहीं बताए गए, इस नीति का केंद्र उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने पर है। राज्य अपनी रणनीतिक स्थिति और कार्यबल का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद रख रहा है।

इस पहल से उम्मीद है कि निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करके और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में पिछले रुकावटों का समाधान होगा। सरकार की उम्मीद है कि यह ढांचा क्षेत्र में रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय बाजार में दीर्घकालिक विकास बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अत्यंत आवश्यक हैं। आने वाले हफ्तों में हितधारकों द्वारा कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी का ध्यान से मूल्यांकन किया जाएगा।

राजनीति

पश्चिम बंगाल CM सुवेंदु: 31 दिसंबर तक मिलेगी CAA के तहत नागरिकता



पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पात्र आवेदकों को 31 दिसंबर तक नागरिकता प्रदान करने का संकल्प रखती है। यह बयान प्रशासन के उस प्रयास को उजागर करता है जिसका उद्देश्य राज्य में लंबित आवेदनों का प्रोसेसिंग तेज करना है।

मुख्यमंत्री के इस बयान में CAA की धाराओं के तहत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने की समयसीमा का उल्लेख किया गया है। वर्ष के अंत तक एक विशिष्ट तिथि निर्धारित करके, राज्य प्रशासन ने आवेदकों को उनके मामलों की स्थिति के बारे में स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास किया है।

यह कदम केंद्र सरकार की नीति के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन का हिस्सा है। राज्य प्रशासन ने नागरिकता प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए काम किया है।

राजनीति

पूर्व सीईसी एस.वाई. कुरैशी का दावा: पश्चिम बंगाल चुनाव कानूनी रूप से अमान्य



पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एस.वाई. कुरैशी ने हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की कानूनी वैधता पर गंभीर चिंताओं का प्रकट किया है। एक महत्वपूर्ण बयान में, उन्होंने दावा किया है कि चुनावों का संचालन आवश्यक कानूनी मानकों को पूरा नहीं करता है, जिससे उन्हें उनके मूल्यांकन के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

पूर्व सीईसी के इन शब्दों ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया विवाद जोड़ दिया है। चुनाव प्रक्रिया की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाकर, उन्होंने संभावित प्रक्रियात्मक या संवैधानिक अनियमितताओं पर प्रकाश डाला है, जिनका मानना है कि वे परिणाम की अखंडता को कमजोर करती हैं।

यह घोषणा भारत भर के कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक हितधारकों का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है। यह बयान पश्चिम बंगाल के चुनावों के प्रशासनिक संभाल पर एक औपचारिक आलोचना के रूप में कार्य करता है, जिससे वोटिंग प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन कानूनों के पालन पर चर्चाएं प्रोत्साहित होती हैं।

हालांकि यह बयान एक पूर्व अधिकारी से आया है, लेकिन यह उनके भारत के निर्वाचन प्रक्रियाओं पर नजर रखने वाले पूर्व भूमिका के कारण महत्वपूर्ण है। अब ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कानूनी अधिकारी और राजनीतिक दल अमान्यता के इन आरोपों का प्रतिक्रिया कैसे देंगे।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल ने औद्योगिक भूखंडों के लिए GIS-आधारित लैंड बैंक की योजना बनाई



पश्चिम बंगाल सरकार एक व्यापक लैंड बैंक बनाने की संभावना पर विचार कर रही है, जिसमें भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) के ज़रिये सभी उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों को डिजिटल रूप में दर्शाया जाएगा। इस डेटाबेस से निवेशकों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपयुक्त साइटों की जानकारी मिल सकेगी, जिससे कई बार स्थल पर जाने की आवश्यकता कम होगी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि GIS-आधारित प्रणाली भूमि के स्वामित्व, बुनियादी ढाँचे की पहुँच और नियामक मंज़ूरी जैसी जानकारी को एक साथ दिखाएगी, जिससे ड्यू-डिलिजेंस प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे औद्योगिक भूमि के आवंटन में समय की बचत होगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

यह कदम राज्य के विनिर्माण को पुनर्जीवित करने और नई निवेश प्रवाह को आकर्षित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो हाल के धीमे विकास को उलटने की दिशा में है। भूमि-सूचना को आसानी से उपलब्ध कराकर सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहती है।

इन विवरणों को NDTV के एक विश्लेषणात्मक लेख में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लैंड बैंक को बंगाल में औद्योगिक पुनरुत्थान के उत्प्रेरक के रूप में बताया गया है।

राजनीति

कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर देर रात हंगामा



कल रात कोलकाता में त्रिनमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर हंगामा हुआ। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह पिछले छह महीनों में उन पर हुए सातवें हमले का मामला है। उन्होंने अपने घर पर हमला करने वालों को अज्ञात बताया है। भाजपा ने इस घटना को 'ड्रामा' कहकर खारिज कर दिया है और बनर्जी के दावों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है।

धर्म

पश्चिम बंगाल में ईसाई समुदाय ने उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया



पश्चिम बंगाल में ईसाई समूहों ने कथित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के सदस्य शामिल हुए, जो अपनी शिकायतें व्यक्त करने और लक्षित उत्पीड़न को खत्म करने की मांग करने के लिए एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपने धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा और हिंसा और धमकी की रिपोर्ट की गई घटनाओं की जांच की मांग की। यह स्थिति भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के बारे में चल रहे बहस पर ध्यान आकर्षित करती है।

धर्म

पश्चिम बंगाल सीएम ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए



मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के पुराने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित निधि घोषित किया। यह निधि विभिन्न मंदिरों में व्यापक नवीनीकरण और पुनर्स्थापना परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी। यह घोषणा एक जनसभा के दौरान की गई थी, जहाँ मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। जीर्णोद्धार के लिए विशिष्ट मंदिरों और धन आवंटन के बारे में विवरण आने वाले दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है।

बिज़नेस

तेंगखाट टैंक फार्म में आग लगने पर ऑयल इंडिया ने जांच समिति बनाई



ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अपने तेंगखाट टैंक फार्म में हुई आग की घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस निर्णय का उद्देश्य घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करना और वहां लागू सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करना है।

कंपनी ने बताया कि जांच समिति आग के मूल कारणों और मौजूदा सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घटना के दौरान सभी नियामक मानकों और आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन किया गया था।

तेंगखाट क्षेत्र में तेल उत्पादों के भंडारण और वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हालांकि आग पर तुरंत नियंत्रण हासिल किया गया है, लेकिन अब ध्यान पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विस्तृत तकनीकी विश्लेषण पर केंद्रित है।

ऑयल इंडिया ने सुरक्षा और अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है, यह संकेत देते हुए कि जांच समिति के निष्कर्षों का उपयोग भविष्य में अपने संचालन स्थलों पर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

शिक्षा

पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के दायरे में लाया



पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के ढांचे के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य इन संस्थानों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की वेतन और भत्तों की संरचना को मानकीकृत करना है।

इस निर्णय से राज्य के हज़ारों विश्वविद्यालय कर्मचारियों की वित्तीय सुविधाओं पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। राज्य प्रशासन द्वारा उनके वेतन स्तरों को राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समायोजित करने से भारत के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ समानता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क रही हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर वेतन और संरचित विकास के लिए लंबे समय से चल रही मांगों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय स्टाफ को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल के नए उद्योग नीति में टेक और क्लाइमेट पर फोकस, जमीन का मुद्दा बना बड़ा सवाल



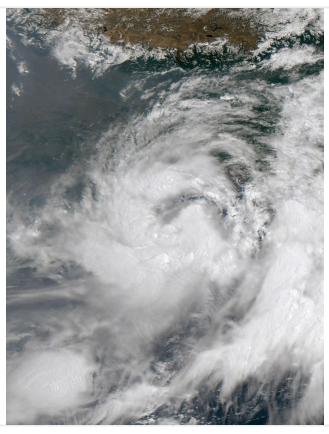
पश्चिम बंगाल ने एक नई औद्योगिक नीति पेश की है, जिसमें तकनीक और जलवायु स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति को इन आधुनिक क्षेत्रों में सकारात्मक प्रगति दर्ज करने के लिए उल्लेखनीय माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य को निवेश के लिए एक आधुनिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। विशेष रूप से, जमीन की उपलब्धता और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति को उन बड़े सवालों के रूप में उठाया गया है, जिन्हें नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए हल करने की आवश्यकता है।

हालांकि टेक और क्लाइमेट पर किए गए प्रयासों को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण और ऊर्जा स्थिरता से जुड़े व्यावहारिक चुनौतियां अभी भी क्षेत्र में विस्तार पर विचार कर रहे व्यवसायों के लिए मुख्य चिंता का विषय बनी हुई हैं।

मौसम

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना, पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 28 अक्टूबर से भारी बारिश



बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है, हाल के रिपोर्टों के अनुसार। यह प्रणाली 28 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश लाने की उम्मीद है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासी आने वाले मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए।

स्वास्थ्य

फर्जी डॉक्टरों पर रोक लगाने के लिए पश्चिम बंगाल में 'नाउ योर डॉक्टर' योजना की शुरुआत



पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली की अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए एक नई 'नाउ योर डॉक्टर' योजना की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन चिकित्सकों की पहचान करना है जो उचित रूप से पंजीकृत नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, या अपनी ड्यूटी पर अक्सर अनुपस्थित रहते हैं।

चिकित्सा पंजीकरण प्रमाणपत्रों के जारी करने और सत्यापन में अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के बीच यह घोषणा एक महत्वपूर्ण समय पर की गई है। मौजूदा निगरानी तंत्र में खालियों को उजागर करने वाली शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे अयोग्य व्यक्ति संभवतः चिकित्सा व्यवसाय करने में सक्षम हो जाते हैं।

राज्य प्रशासन का इरादा इस सिस्टम का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना है कि मरीज उपचार लेने से पहले अपने डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स की सत्यापन कर सकें। फर्जी, मृत और अनुपस्थित चिकित्सकों को निशाना बनाकर, सरकार का लक्ष्य चिकित्सा पेशे में जनता का विश्वास बहाल करना है।

हालांकि कार्यान्वयन के विशिष्ट तकनीकी विवरण अभी अंतिम रूप दिए जा रहे हैं, मुख्य ध्यान पारदर्शिता पर केंद्रित है। यह योजना एक विश्वसनीय डेटाबेस बनाने का प्रयास है, जिससे राज्य के भीतर चिकित्सकों की सक्रिय स्थिति और प्रामाणिकता की जांच की जा सके।

बिज़नेस

पश्चिम बंगाल ने निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए नया उद्योग नीति जारी किया



पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य की आर्थिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना और स्थानीय कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण रोज़गार के अवसर सृजित करना है।

यह रणनीतिक कदम प्रशासन के व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नियामक प्रक्रियों को सरल बनाने और लक्षित प्रोत्साहनों को प्रदान करके, राज्य को पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनाने की उम्मीद है।

इस नीति से उन क्षेत्रों को आकर्षित करने की उम्मीद है जो लागत-प्रभावी निर्माण और संचालन आधार खोज रहे हैं। अधिकारियों की उम्मीद है कि औद्योगिक विकास पर इस नए जोर से नौकरियों में ملموس वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र की समग्र आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी।

नौकरी

बंगाल की 7वीं वेतन आयोग में राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों को शामिल



पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की 7वीं वेतन आयोग की दायरा तय कर लिया है, जिसमें अब राज्य-सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। आयोग की इस मंडाट में विस्तार से उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों को राज्य के एकीकृत वेतन समीक्षा ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा।

पहले, इन श्रेणियों के कर्मचारी अक्सर इस तरह की व्यापक वेतन समीक्षाओं से बाहर रहते थे, जिससे अन्य राज्य सरकार कर्मचारियों की तुलना में वेतन संरचना में असमानता पैदा हो जाती थी। इनकी शमूल ी से राज्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, विशेष रूप से शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में काम करने वालों के लिए वेतन स्केल और भत्तों को मानकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।

हजारों गैर-शिक्षक कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने न्यायपूर्ण वेतन के लिए लंबे समय से आंदोलन किया है। आयोग की सिफारिशें संभवतः राज्य के वित्तीय योजनाबद्ध प्रभावित करेंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के भीतर एक महत्वपूर्ण कार्यबल के संशोधित वेतन संरचनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

यह कदम राज्य के प्रशासनिक वेतन प्रणालियों को आधुनिकी करने और सरकारी सेवा के विभिन्न शाखाओं में समान उपचार सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों से मेल खाता है।

रक्षा

राजनाथ सिंह ने बागडोग्रा में IAF योद्धाओं के देशभक्ति गीत की प्रशंसा की



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय वायु सेना (IAF) के जवानों द्वारा गाए गए एक भावनात्मक देशभक्ति गीत का वीडियो साझा किया। इस क्लिप में वायु सेना के योद्धाओं को समर्पण के साथ गाने देखा जा सकता है, जो सैन्य जीवन में कलात्मक प्रतिभा और राष्ट्रीय सेवा के संगम को दर्शाता है।

अपने संदेश में, सिंह जी ने IAF सदस्यों की संगीत प्रतिभा की सराहना की और कहा कि यह उनके देश की सेवा के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने इस प्रस्तुति को सशस्त्र बलों के मनोबल और आत्मा का प्रमाण बताया।

बागडोग्रा वायु सेना स्टेशन पर वायु सेना के योद्धाओं को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने सतर्कता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की बदलती प्रकृति और वर्तमान परिदृश्य में गलत सूचनाओं के लगातार खतरे के बारे में बताया।

सिंह जी ने आधुनिक युद्ध में संचालनात्मक तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया और जवानों से सतर्क रहने और तैयार रहने की अपील की। बागडोग्रा में उनके बयान ने यह याद दिलाया कि हालांकि मनोबल और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा की नींव सैन्य तैयारी ही है।

शिक्षा

स्वामी विवेकानंद के पोस्टर को विरूपित करने पर प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय ने दो छात्रों को निष्कासित किया



कोलकाता स्थित प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय ने अपने दो छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें संस्थान से निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय स्वामी विवेकानंद की तस्वीर वाले एक पोस्टर को कथित तौर पर विरूपित करने की घटना के बाद लिया गया है।

इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, निष्कासित छात्रों को विश्वविद्यालय में किसी भी आगे की शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कदम ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति सम्मान बनाए रखने और परिसर में अनुशासन कायम रखने के विश्वविद्यालय के रुख को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने विरूपण की विशिष्ट प्रकृति या घटना की समय-सीमा के संबंध में अतिरिक्त विवरण जारी नहीं किया है।

राजनीति

ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के आवास पर हमले की निंदा की



पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुई एक घटना की कड़ी निंदा की है। बनर्जी ने इस घटना को 'पूर्ण गुंडागर्दी' करार देते हुए इसकी निंदा की।

यह हमला अभिषेक बनर्जी के घर पर काली पूजा के उत्सव से ठीक पहले हुआ। मुख्यमंत्री का बयान इस घटना को प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिए जाने को दर्शाता है, खासकर एक प्रमुख त्योहार से पहले इसके समय को देखते हुए।

राजनीति

अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन समारोह में घर पर रिवॉल्वर लेकर पहुंचा व्यक्ति, कोलकाता में हंगामा



शुक्रवार की देर रात कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के निवास पर एक तनावपूर्ण स्थिति सामने आई। जब सांसद अपने जन्मदिन समारोह में शामिल थे, तब एक व्यक्ति उनके घर पर रिवॉल्वर लेकर पहुंचा, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया।

गवाहों के अनुसार, हथियार की उपस्थिति ने मौजूद मेहमानों और सुरक्षा कर्मीओं में तुरंत अफरा-तफरी मचा दी। सुरक्षा दल और स्थानीय पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका और स्थिति पर नियंत्रण हासिल किया।

कोलकाता पुलिस ने इस घटना की सूचना दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस उस व्यक्ति की पहचान और राजनीतिक हस्तियों के निजी निवास पर प्रतिबंधित हथियार लाने के पीछे की प्रेरणा की जांच कर रही है।

राजनीति

सुवेन्दु आडिगरी ने बौद्धदेव भट्टाचार्य की ज़मीन अधिग्रहण नीति को उद्योगों के गिरावट का कारण बताया



नवंबर 5 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेन्दु आडिगरी ने राज्य की घटती औद्योगिक संभावनाओं का कारण बौद्धदेव भट्टाचार्य के शासनकाल में लागू ज़मीन अधिग्रहण नीति बताया। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए ज़मीन के बलपूर्वक अधिग्रहण ने निवेशकों को दूर किया और विकास को रोक दिया।

यह बयान पश्चिम बंगाल के घटते औद्योगिक उत्पादन के बढ़ते चिंताओं के बीच आया, जहाँ आडिगरी ने बताया कि इन नीतियों की विरासत ने व्यावसायिक माहौल पर स्थायी असर छोड़ा है।

उद्योग समूहों और विपक्षी दलों ने सुधारों की मांग की है, सरकार से ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रियाओं को निवेश-अनुकूल बनाने का आग्रह किया है। यह टिप्पणी पिछले लेफ्ट फ्रंट सरकार की औद्योगिक नीति पर एक आलोचना के रूप में देखी जा रही है।

आडिगरी के इस बयान से राज्य के आगामी औद्योगिक नीति ढाँचे पर असर पड़ने की संभावना है, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण मानदंडों को आसान बनाने और निवेश माहौल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।